माननीय न्यायालय रामेश्वर सिंह मलिक, जे.

रतन लाल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

सी डब्ल्यूपी नं. 2011 का 18981

जुलाई 10,2013

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट क्षेत्राधिकार-क्या उपायुक्त को नगर निगम के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के ट्यूबवेल के कब्जे, नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र है। - उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के अनुसरण में की गई विवादित भूमि का सीमांकन-याचिकाकर्ताओं को उक्त भूमि के कब्जे में पाया गया-कारण बताओ नोटिस या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना ट्यूबवेल का कब्जा, नियंत्रण और प्रबंधन लेने के लिए उपायुक्त का आदेश पारित किया गया-आयोजित, ऑडी अल्टरम पार्टेम के सुनहरे नियम का उल्लंघन किया गया-कारण किसी भी निर्णय की आत्मा है-विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और रद्द कर दिया गया है-रिट याचिका की अनुमति है।

माना गया कि यह रिकॉर्ड पर निर्विवाद हो गया है कि उपायुक्त ने तहसीलदार को सीमांकन करने और सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नगर निगम से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। हालाँकि, न तो कब्जे में सच्चे मालिकों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, i.e., याचिकाकर्ताओं, और न ही उन्हें सुनने का कोई अवसर दिया गया था, विवादित आदेश पारित करने से पहले। ये सरल लेकिन मजबूत कारण थे, कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील अपने तर्कों को क्यों साबित नहीं कर सके।

(Para 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी भी राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश न्यायसंगत और अच्छी तरह से तर्कपूर्ण होना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में एक मनमाना आदेश पारित किया गया है। यहां तक कि वर्तमान मामले में ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सुनहरे नियम का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। यह कहने के पश्चात्, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उपायुक्त, फरीदाबाद-प्रत्यर्थी संख्या. 3 द्वारा पारित दिनांक 16.9.2011 (अनुलग्नक पी-5) के आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(Para 10)

वर्तमान मामले में, फरीदाबाद के उपायुक्त, विवादित आदेश पारित करते समय कोई भी कारण दर्ज करने में विफल रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि फरीदाबाद के उपायुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश न केवल मनमाना था, बल्कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर भी था। इस प्रकार, विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(Para 14)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविंद कश्यप।

अजय गुलाटी, डीएजी हरियाणा।

रामेश्वर सिंह मलिक, जे।

1) याचिकाकर्ताओं ने फरीदाबाद के उपायुक्त द्वारा पारित दिनांक 16.9.2011 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को चुनौती दी है, जिससे नगर निगम, फरीदाबाद को याचिकाकर्ताओं के ट्यूबवेल का कब्जा, नियंत्रण और प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह उनकी अपनी भूमि में स्थापित किया गया था। इस प्रकार, वर्तमान सुगमता में शामिल छोटा मुद्दा यह है कि क्या उपायुक्त के पास याचिकाकर्ताओं के ट्यूबवेल के कब्जे, नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र था।
2) पहले तथ्य। याचिकाकर्ताओं का अनुरोधित मामला यह है कि वे कब्जे वाले मालिकों को खसरा नं. 1434, जिसे 538 के रूप में नया नंबर आवंटित किया गया है। खसरा नं. अक्स शाजरा के अनुसार, 1390 एक नकली दस्तावेज था। यह साइट प्लान अनुलग्नक पी-1 में दर्ज किया गया है। स्वर्गीय श्री. श्री के पुत्र देस राज। याचिकाकर्ताओं के पिता तुलसी ने 20 साल से अधिक समय पहले अपनी जमीन पर ट्यूबवेल लगाया था। उत्तरदाताओं नं. 5 और 6, जो याचिकाकर्ताओं के संपार्श्विक थे, ट्यूबवेल की स्थापना से खुश नहीं थे। वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक या दूसरी झूठी शिकायत करते थे। इसके बाद उन्होंने सीडब्ल्यूपी नं. 2011 का 6979 इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के रूप में, जिसका इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 25.4.2011 के आदेश द्वारा निपटारा किया गया था। (Annexure P-2).
3) इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, उपायुक्त, फरीदाबाद-प्रत्यर्थी संख्या. 3 ने तहसीलदार को सीमांकन करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को खसरा नं. 1434 और इसकी नई खसरा संख्या 538 थी जिसमें विचाराधीन ट्यूबवेल स्थित था। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं को ट्यूबवेल के मालिकों के रूप में पाया गया था, उपायुक्त ने अपने विवादित आदेश में फरीदाबाद नगर निगम को ट्यूबवेल के कब्जे, नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने का निर्देश दिया। न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। इस प्रकार, उपरोक्त आक्षेपित आदेश के विरुद्ध व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई है।
4) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और उसके अनुसार, लिखित बयान दायर किए गए थे।
5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि विवादित आदेश मनमाना होने के अलावा इसके अधिकार क्षेत्र के बिना था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विवादित आदेश पारित करते समय उपायुक्त द्वारा प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि तहसीलदार की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, एक बार याचिकाकर्ताओं का स्वामित्व और कब्जा विधिवत स्थापित हो जाने के बाद, उपायुक्त को याचिकाकर्ताओं के ट्यूबवेल के कब्जे, नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने का कोई अधिकार नहीं था। यह जिला प्रशासन की ओर से ज्यादती के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके कारण विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए था, अंत में, वह वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देकर विवादित आदेश को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना करता है।
6) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने न्यायालय द्वारा पूछे गए विशिष्ट प्रश्न का सामना किया कि विवादित आदेश कानूनी रूप से कैसे टिकाऊ था, वे विवादित आदेश के समर्थन में कोई सार्थक तर्क देने में विफल रहे। जब एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया या विवादित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर क्यों

नहीं दिया गया, तो प्रतिवादियों के विद्वान वकील के पास कोई जवाब नहीं था। he हालाँकि, उनका कहना है कि विवादित आदेश में कुछ भी अवैध नहीं था और रिट याचिका खारिज होने योग्य थी।

7) मैंने पक्षकारों के विद्वत वकील को काफी विस्तार से सुना, सहजता के अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारशील विचार करने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित एक से अधिक कारणों से अनुमति देने योग्य है।

8) यह रिकॉर्ड पर निर्विवाद हो गया है कि उपायुक्त ने तहसीलदार को सीमांकन करने और सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नगर निगम से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। हालाँकि, विवादित आदेश पारित करने से पहले न तो कब्जे वाले वास्तविक मालिकों, यानी याचिकाकर्ताओं को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था। ये सरल लेकिन मजबूत कारण थे, कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील अपने तर्कों को क्यों साबित नहीं कर सके।

9) यह कानून का तय प्रस्ताव है कि किसी भी राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश न्यायसंगत और अच्छी तरह से तर्कपूर्ण होना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में एक मनमाना आदेश पारित किया गया है। यहां तक कि वर्तमान मामले में ऑडी अल्टेरम पार्टेम के सुनहरे नियम का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। यह कहने के पश्चात्, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उपायुक्त, फरीदाबाद-प्रत्यर्थी संख्या. 3 द्वारा पारित दिनांक 16.9.2011 (अनुलग्नक पी-5) के आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। विवादित आदेश में ही सीमांकन रिपोर्ट के बारे में चर्चा इस प्रकार हैः -

"बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तहसीलदार, फरीदाबाद को खसरा नं. में निजी ट्यूबवेल के स्वामित्व के संबंध में निसंदेही रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया जाए। 1434, कट्टन पहाड़ी देश राज कॉलोनी, गाँव अनंगपुर
निसंदेही/सीमांकन रिपोर्ट 18,8.20 जज को तहसीलदार, फरीदाबाद से सहायक समेकन अधिकारी गुड़गांव की रिपोर्ट के साथ मेमो नं। 386 दिनांक 17.8.2011 का उल्लेख करते हुए कि समेकन से पहले खसरा नं. 1434 (2 कनाल 10 मारिया) शामलात देह के स्वामित्व में था, लेकिन समेकन के दौरान नया खसरा नं। चकबंदी रजिस्टर में 538 का उल्लेख है और अब यह एक निजी भूमि है और याचिकाकर्ताओं के पिता के साथ-साथ अन्य सह-शेयरधारकों को भूमि का मालिक दिखाया गया है। "

10) रिट याचिका के पैरा 8 और 12 में याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी कारण बताओ नोटिस को जारी न करने या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बारे में किए गए प्रासंगिक कथन, जो निम्नानुसार हैंः –

“कि प्रत्यर्थी संख्या. 3 ने याचिकाकर्ताओं को, जो उक्त ट्यूबवेल/बोर के वास्तविक स्वामी हैं, कोई नोटिस जारी किए बिना और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसी का उपयोग किए बिना और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना, दिनांक 16.9.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के ट्यूबवेल/बोर को अधिग्रहित करने का आदेश दिया है, दिनांक 16.9.2011 के आक्षेपित आदेश की एक प्रति अनुलग्नक पी-5 के रूप में संलग्न की गई है।“

“याचिका में कहा गया है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है और (उन्होंने विवादित आदेश पारित किया है जो राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं का व्यक्तित्व/उचित रूप से है जिसे विवादित आदेश पारित करके नहीं लिया जा सकता है)”

11) उपायुक्त प्रत्यर्थी संख्या. 3 की ओर से ढेर किए गए उत्तर में, उन्होंने उपरोक्त कथनों और उत्तर के पैरा 8 और 12 का खंडन नहीं किया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया हैः-"कि पैरा नं. रिट याचिका के 8

गलत हैं और इसलिए अस्वीकार कर दिए गए हैं। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 16.9.20// का आदेश तत्कालीन उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पारित किया गया है, आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक/6.9.201 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नगर निगम को दिनांक 16.9.20/1 के आदेश द्वारा कॉलोनी के लिए सार्वजनिक हित और पेयजल के सामान्य प्रयोजन के लिए निजी अवैध ट्यूबवेल को अपने अधिकार में लेना चाहिए। xxx xxx XXX वह पैरा नंबर की सामग्री। रिट याचिका में से 2 गलत हैं और इसलिए अस्वीकार कर दिए गए हैं। तथापि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक/6.9.20/1 का आदेश तत्कालीन उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पारित किया गया है, आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 6.9.20/1 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नगर निगम ने 1 6.9.20 11 के आदेश द्वारा कॉलोनी के लिए सार्वजनिक हित और पेयजल के सामान्य प्रयोजन के लिए निजी अवैध ट्यूबवेल पर झील बनाई है। "

12) प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा उपरोक्त कथनों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या. 3 की ओर से किए गए कथनों से कोई विश्वास पैदा नहीं होता है, क्योंकि वह ट्यूबवेल का कब्जा, नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद को निर्देश देते हुए इसके कम ठोस कारण बताने में बुरी तरह विफल रहा है। विवादित आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार हैः-"एमसी आई7 से रिपोर्ट देर से प्राप्त हुई थी, इसलिए देरी हुई। इसलिए, दोनों पक्षों (याचिकाकर्ताओं और एमसीई) को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एमसीआई7 को सार्वजनिक हित और कॉलोनी के लिए शराब पीने के सामान्य उद्देश्य के लिए निजी अवैध ट्यूबवेल का अधिग्रहण करना चाहिए।"
13) जैसा कि उचित रूप से कहा गया है, कारण किसी भी निर्णय की आत्मा है। हालांकि, वर्तमान मामले में, फरीदाबाद के उपायुक्त, विवादित आदेश पारित करते समय कोई भी कारण दर्ज करने में विफल रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि फरीदाबाद के उपायुक्त द्वारा पारित विवादित आदेश न केवल मनमाना था, बल्कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर भी था। इस प्रकार, विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।
14) कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।
15) ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार, उपायुक्त, फरीदाबाद प्रत्यर्थी संख्या. 3 द्वारा पारित दिनांक 16.9.2011 (अनुलग्नक पी-5) को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तथापि, प्रत्यर्थी राज्य का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16) नतीजतन, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा